ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

भारत में बढ़ती जनसँख्या एवं समस्याएं

Dr. Panmal Pahariya

Associate Professor, Dept. of Geography, Govt. College, Tonk, Rajasthan, India

सार

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इसको नियंत्रित करने की बात कही है। इससे कुछ समय पूर्व ही बजट सत्र में एक नामांकित संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2011 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। निजी विधेयक होने के कारण यह संसद में पारित तो नहीं हो सका किंतु प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात् इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा की जाने लगी है। इस विधेयक में दो बच्चों के जन्म का प्रावधान किया गया है। दो से अधिक बच्चों वाले जनप्रतिनिधि को अयोग्य निर्धारित किया जाएगा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी दो से अधिक बच्चे पैदा न करने का शपथ पत्र देना होगा। हालाँकि ऐसे कर्मचारी जिनके पहले से ही दो से अधिक बच्चे हैं उनको इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को दो बच्चों की नीति को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न विनियमों की भी बात इस विधेयक में की गई है। किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुँच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी ग़ैर-अनुपातित वृद्धि होने लगती है, इसलिये इसमें स्थिरता लाना ज़रूरी होता है। संसाधन एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। संसाधनों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, में यह दर क़रीब 2.1 है जिसे स्थिरता दर माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य हैं, इनमें कुल प्रजनन क्षमता दर चार से ज़्यादा है। यह भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है। जब किसी भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो, तो ऐसे स्थान से लोग रोज़गार तथा आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं। किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है, विभिन्न क्षेत्रों में उपजा क्षेत्रवाद कहीं न कहीं संसाधनों के लिये संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

परिचय

आर्थिक सर्वेक्षण 2012अलग दृष्टिकोण

आर्थिक सर्वेक्षण 2012 में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है। वर्ष 1971-81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर जहाँ 2.5 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011में घटकर 1.3 प्रतिशत पर आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में जनसांख्यिकीय के ट्रेंड की चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे राज्य जहाँ एतिहासिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, में भी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। दक्षिण भारत के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम तथा हिमाचल प्रदेश में वार्षिक वृद्धि दर 1 प्रतिशत से भी कम है। सर्वेक्षण के अनुसार, आने वाले दो दशकों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट की संभावना है, साथ ही कुछ राज्य वृद्ध समाज की स्थिति की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आशावादी रवैया रखता है बल्कि भारत में नीति निर्माण का फोकस भविष्य में बढ़ने वाली वृद्धों की संख्या की ओर करने का सुझाव देता है।[1]

जनसांख्यिकीय लाभांश या जनसांख्यिकीय अभिशाप

किसी देश में युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है। भारत में मौजूदा समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है यदि इस आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाए तो यह भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करेगा। किंतु यदि शिक्षा गुणवत्ता परक न हो, रोज़गार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हों तो बड़ी कार्यशील आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अतः विभिन्न देश अपने संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या अत्यधिक है किंतु उसके लिये रोज़गार के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है।

बढ़ती आबादी की प्रमुख चुनौतियाँ

- स्थिर जनसंख्या: स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- जीवन की गुणवत्ता: नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा, अनाजों एवं खाद्यान्नों का अधिक-से-अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा।
- नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके समायोजित करने के लिये भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है तथा इसके लिये भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।[2]
- जनसांख्यिकीय विभाजन: बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का मज़बूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, लेकिन भारत की कम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतिशत) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
- सतत् शहरी विकास: देश की शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी, साथ ही पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
- असमान आय वितरण : आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगी।

गरीबी तथा जनसंख्या वृद्धि में महत्त्वपूर्ण संबंध

परिवार का स्वास्थ्य, बाल उत्तरजीविता और बच्चों की संख्या आदि माता-पिता (विशेषकर माता) के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर से गहराई से संबद्ध हैं। इस प्रकार कोई दंपति जितना निर्धन होगा, उसमें उतने अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति होगी। इस प्रवृत्ति का संबंध लोगों को उपलब्ध अवसरों, विकल्पों और सेवाओं से है। गरीब लोगों में अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति इसलिये होती है क्योंकि इस वर्ग में बाल उत्तरजीविता निम्न है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हमेशा से उच्च बनी रही है, बच्चे आर्थिक गतिविधियों में सहयोग देते हैं और इस प्रकार परिवार की आर्थिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 (2014) के अनुसार, न्यूनतम वेल्थ क्विंटिल (Wealth Quintile) की महिलाओं के उच्चतम वेल्थ क्विंटिल की महिलाओं की उपेक्षा औसतन 1.6 गुना अधिक बच्चे पाए जाते हैं। इस प्रकार समृद्धतम से निर्धनतम की ओर बढने पर 1.5 के स्थान पर 3.2 की प्रजनन दर पाई जाती है। इसी प्रकार प्रति महिला बच्चों की संख्या महिलाओं की विद्यालयी शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ घटती जाती है। 12 या उससे अधिक वर्षों तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त महिलाओं के औसतन 1.7 बच्चों की तुलना में विद्यालय नहीं गई महिलाओं में बच्चों की औसत दर 3.1 रही। इससे उजागर होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और असमानता का प्रजनन दर से गहरा संबंध है तथा स्वास्थ्य व शिक्षा तक कम पहुँच रखने वाले लोग निर्धनता के कुचक्र में फँसे रहते हैं और अधिकाधिक बच्चों को जन्म देते हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में ही प्रति व्यक्ति अस्पताल बिस्तरों की न्यूनतम उपलब्धता की भी स्थिति है।[3]

जनसंख्या नियंत्रण- उपाय

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के बावजूद भारत की बढ़ती जनसंख्या एक सच्चाई है, जो वर्ष 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विभिन्न नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन परिणामों को रोकने के लिये आवश्यक है कि

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

जनसंख्या को नियंत्रित करके वृद्धि दर को स्थिर किया जाए। निम्नलिखित उपायों से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को रोका जा सकता है-

- आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है।
- महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना।
- भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे परिवारों को बच्चे गोद लेने के लिये प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिये प्रेरित करना। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
- भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाहत में अधिक-से-अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।
- भारतीय समाज में किसी भी दंपत्ति के लिये संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपत्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है, यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगा।
- सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था में सहारे के रूप में बच्चों का होना आवश्यक माना जाता है। किंतु मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के कारण इस विचार में बदलाव आया है। यह कारक भी जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी हो सकता है।
- परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि उच्च जीवन स्तर वाले लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं।
- भारत में शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि के साथ व्यूत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित माना जाता है। यदि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी साबित होगा।[4]
- भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाए तो यह जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर साधन हो सकता है।
- भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर है इसलिये परिवार नियोजन के लाभों से अवगत नहीं है। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे- टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिये।
- सरकार को ऐसे लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिये जो परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं तथा छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या समर्थन

भारत ने जनसंख्या को किसी समस्या और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं देखा है बल्कि एक संपन्न संसाधन के रूप में देखा है जो एक विकास करती अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। इसे समस्या और नियंत्रण की शब्दावली में देखना और इस दृष्टिकोण से कार्रवाई करना राष्ट्र के लिये अनुकूल कदम नहीं होगा। यह दृष्टिकोण अब तक कि प्रगति को बाधित कर देगा और एक कमज़ोर व बदतर स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के लिये ज़मीन तैयार करेगा। यह परिदृश्य उस उद्देश्य के विपरीत होगा जिसे आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करने की इच्छा है। वर्तमान में 23 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों (दक्षिण भारत के सभी राज्य सहित) में प्रजनन दर पहले ही प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर के नीचे पहुँच चुकी है। इस प्रकार नियंत्रण के बजाय समर्थन की नीति अधिक कारगर होगी।

अतीत से सबक

IJMRSETM

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

स्वतंत्र भारत में दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान वर्ष 1951 में आरंभ किया गया। किंतु इससे सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किये गए। इन प्रयासों में कई अमानवीय तरीकों का उपयोग किया गया। इससे न सिर्फ यह कार्यक्रम असफल हुआ बल्कि लोगों में नियोजन और उसकी पद्धति को लेकर भय का माहौल उत्पन्न हो गया जिससे कई वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यह 130 करोड़ को भी पार कर चुकी है, साथ ही वर्ष 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में भारत के समक्ष तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। इस स्थिति में जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय अभिशाप में बदलता जा रहा है। इसी स्थिति को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस समस्या को दोहराया है। हालाँकि जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है किंतु इसके नियंत्रण के लिये क़ानूनी तरीका एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रयास करने चाहिये। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिये।

विचार-विमर्श

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव

भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, संपत्ति तथा धन के आधार पर कुल प्रजनन दर (TFR) में विभिन्नता देखने को मिलती है। यह सबसे निर्धन समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला तथा उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला है। इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती है।जनसंख्या वृद्धि की वज़ह से गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा आती है। इससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (SDG) संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती आबादी की प्रमुख चुनौतियाँ

- स्थिर जनसंख्या : स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।[5]
- जीवन की गुणवत्ता : नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा, अनाजों और खाद्यान्नों का अधिक-से-अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा।
- नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके समायोजित करने के लिये भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिये भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।
- जनसांख्यिकीय विभाजन : बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का मज़बूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, लेकिन भारत की कम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतिशत) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
- सतत शहरी विकास : देश की शहरी आबादी 87.7 मिलियन तक हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इन सभी के लिये पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
- असमान आय वितरण : आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगा।

परिणाम

- भारत को मध्यवर्ती-प्रजनन समूह (Intermediate-fertility Group) वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें विश्व की कुल 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।
- भारत विश्व की कुल जनसंख्या में 273 मिलियन का इज़ाफा करेगा।

जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव

- भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, संपत्ति तथा धन के आधार पर कुल प्रजनन दर (TFR) में विभिन्नता देखने को मिलती है। यह सबसे निर्धन समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला तथा उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला है। इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती है।[6]
- जनसंख्या वृद्धि की वज़ह से गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा आती है। इससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (SDG) संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

बढ़ती आबादी की प्रमुख चुनौतियाँ

- स्थिर जनसंख्या : स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- जीवन की गुणवत्ता : नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा, अनाजों और खाद्यान्नों का अधिक-से-अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा।
- नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके समायोजित करने के लिये भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिये भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।
- जनसांख्यिकीय विभाजन : बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का मज़बूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, लेकिन भारत की कम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतिशत) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
- सतत शहरी विकास : देश की शहरी आबादी 87.7 मिलियन तक हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इन सभी के लिये पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा।
- असमान आय वितरण : आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगा।

क्या किया जा सकता है

- भविष्य में सभी के लिये खाद्यान्न सुनिश्चित करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण है कि कृषि को लाभकारी बनाया जाए और खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न हो अर्थात् कमोबेश वे स्थिर रहें।
- न्यूनतम मासिक आय (Universal Basic Income) को सुरक्षा कवच के रूप में लागू करना भी बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।[7]
- वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा ताकि उन्हें सतत इस्तेमाल के लिये बचाया जा सके।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

- सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति किसी भी नीति निर्माण का केंद्रबिंदु होना चाहिये।
- अपेक्षाकृत कम आय और घनी आबादी वाले भारत के उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से सीख लेते हुए महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य और कार्यबल में भागीदारी जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।
- जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकारों और मज़बूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है।
- बढ़ती जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) और किशोरों की बढ़ती आबादी सेवा के नए क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर तलाशने में मदद करेगी।
- AMRUT, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी योजनाएँ निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारिक संरचना को बढ़ाने में सहायता करेंगी।

आगे की राह (अन्य संभावित उपाय)

- भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाना होगा। वर्तमान में यह GDP का केवल 1.3% है। कुल स्वास्थ्य बजट में से परिवार कल्याण (नियोजन) पर मात्र 4% ही खर्च होता है और इसमें से भी केवल 1.5% जन्म में अंतर रखने के उपायों पर खर्च किया जाता है।
- बुजुर्ग होती आबादी के लिये निवेश को बढ़ाना होगा, क्योंकि वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी वर्तमान से लगभग 10 गुना अधिक तक बढ़ सकती है।
- शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है, न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये बल्कि प्रजनन क्षमता में गिरावट के लिये भी। बेहतर शिक्षा महिलाओं को परिवार नियोजन के लिये सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
- जब तक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा नहीं होंगी, कोई भी समाज प्रजनन दर में कमी नहीं ला सकता। ऐसे में प्रभावी नीतियाँ बनाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी को रोकना चाहिये।
- ऐसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 140 ऐसे ज़िलों की पहचान करना इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है।
- देश में लैंगिक अनुपात में गिरावट और लड़कियों के प्रति भेदभाव काफी अधिक है। इस मुद्दे पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग लड़का होने की उम्मीद में अधिक संख्या में बच्चों को जन्म न दें।
- परिवार नियोजन के साथ जोड़कर भारत कई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल कर सकता है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम करने के लिये परिवार नियोजन एक प्रोत्साहक और निवारक उपाय है।
- जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को थामने के लिये अलग-अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।[8]

सरकार सहित राजनेताओं, नीति-निर्माताओं और आम नागरिकों, सभी को साथ मिलकर एक कड़ी जनसंख्या नीति बनानी होगी ताकि देश की आर्थिक विकास दर बढ़ती आबादी के साथ तालमेल कायम रख सके।

निष्कर्ष

भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण :

किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वहाँ की जनसंख्या या जनशक्ति का पर्याप्त योगदान होता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर आर्थिक विकास में भी प्रगति हो। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की जनशक्ति वरदान बनने की अपेक्षा अभिशाप बन गयी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जनाधिक्य की समस्या इस समय भारत की सबसे बड़ी आर्थिक व सामाजिक समस्या बन गयी है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 2, Issue 12, December 2015

1. विवाह की सर्वव्यापकता

भारत में विवाह करना एक अनिवार्य सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। भारत में यह बात सभी वर्गों के लोगों में पायी जाती है। विवाह की इस सर्वव्यापकता के कारण हमारे देश में जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ती है।

2. बाल-विवाह की प्रथा

भारत में विवाह की आयु भी कम है। इससे बच्चे उत्पन्न करने की अवधि लम्बी पायी जाती है। अन्य शब्दों में, बाल-विवाह की प्रथा के कारण शादी के बाद माँ की सन्तान उत्पन्न करने की अवधि काफी लम्बी रहती है। साथ ही कम उम्र में शादी करने से लड़के तथा लड़कियों में परिपक्वता नहीं होती है और न ही उन्हें इसके बारे में कोई अनुभव ही होता है। इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है।

3. गर्म जलवायु

हमारे देश की जलवायु गर्म है। इस कारण विशेषकर लड़कियाँ शीघ्र ही तरुणावस्था को प्राप्त कर लेती हैं। साथ ही विवाह एक सामाजिक अनिवार्यतः होने के कारण माता-पिता शीघ्र ही शादी कर देते हैं। इस अवस्था में प्रजनन शक्ति अधिक पायी जाती है। यही कारण है कि गर्म जलवायु वाले देशों में बच्चे अधिक जन्म लेते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का एकमात्र कारण गर्म जलवायु का पाया जाना कहा जाता है।

4. मृत्यु-दर में कमी

पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में मृत्यु-दर में पर्याप्त कमी आयी है। एक अनुमान के अनुसार यह एक-तिहाई रह गयी है। इस कमी के कारण इस प्रकार हैं- (क) अकालों तथा महामारियों में कमी, (ख) स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि, (ग) चिकित्सा व स्वास्थ्य में वृद्धि, (घ) अन्धविश्वास की कमी, (ङ) मनोरंजन के साधनों में विस्तार। इस प्रकार मृत्यु-दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना अनिवार्य है।[7]

5. धार्मिक भावना

हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि का एक धार्मिक कारण भी है। प्रायः हिन्दू धर्म के मानने वालों का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि पुत्र नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिये विवाह एक ओर अनिवार्यता तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा दोनों ही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि में यह भावना सहायक होती है।

6. अशिक्षा तथा अन्धविश्वास

आज भी हमारे देश में शिक्षा का प्रसार कम है। यही कारण है कि अधिकांश समाज के व्यक्ति अब भी 'दूधो नहाओ पूतो फलो' के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग भाग्यवादी हैं। वे सन्तान को भगवान की देन समझते हैं। वे सन्तान निरोध के उपयोग में विश्वास नहीं रखते हैं। इस कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है।

7. निम्न जीवन-स्तर

भारतीय जनसंख्या की वृद्धि का एक कारण यह भी है कि हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है। हम लोगों की आय इतनी कम होती है कि जीवनरक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाना मुश्किल होता है।

8. स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता

भारतीय समाज में अविवाहित स्त्री को हेय की या अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यदि कोई स्त्री अविवाहित रहकर अपनी जीविकोपार्जन के साधन स्वयं जुटाती है तो इसे अनावश्यक रूप से बुरा माना जाता है। इसीलिये बाध्य होकर अपनी जीविका के लिये उसे पुरुष वर्ग का सहारा लेना पड़ता है। अतएव उसे विवश होकर शादी करनी पड़ती है। यही कारण है कि हमारे देश में विवाह सर्वव्यापी है। अतएव यह कहना गलत न होगा कि इस आर्थिक निर्भरता के कारण भी भारतीय समाज में जनसंख्या वृद्धि होती है।

9. निरोधक सुविधाओं का अभाव

अनेक परिवारों में इच्छा रहते हुए भी परिवार नियोजन को नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि लोगों को इन सुविधाओं की बराबर जानकारी नहीं होती है। साथ-ही-साथ यह भी कहना गलत न होगा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि सामान्य जनता उसे खरीदने में असमर्थ रहती है। इस प्रकार भारत में ऐसे सस्ते उपकरणों को सुलभ कराने की आवश्यकता है, ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके।[6]

10. शरणार्थियों तथा विदेशों से भारतीयों का आगमन

वर्तमान समय में देश की जनसंख्या की समस्या ने और अधिक रूप धारण कर लिया है। इस कारण देश में विदेशों से भारतीयों का आगमन है तथा पर्याप्त मात्रा में शरणार्थियों का आना है। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलाया, ब्रिटेन, केनिया, युगाण्डा, म्यांमार तथा पाकिस्तान से पर्याप्त मात्रा में लोग भारत में आये। इसके फलस्वरूप भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा अन्य समस्याओं का जन्म हुआ। इससे देश के आर्थिक विकास में बाधा आयी है।उपर्युक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। वास्तव में देश में निर्धनता, निम्न जीवन-स्तर, बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्न का अभाव, आवास, चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी आदि को जन्म जनाधिक्य ने ही दिया है। इसीलिये कहा जाता है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बाधा है।

जनसंख्या समस्या :

इससे निम्नलिखित समस्याओं में वृद्धि हुआ है-

(i) आर्थिक विकास के लिये देश में सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूँजी-निर्माण है, किन्तु देश में जनसंख्या की वृद्धि के कारण पूँजी के निर्माण की गति पर्याप्त धीमी होती है। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का कार्य मन्द हो गया है।

(ii) जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव उत्पादन तकनीक पर भी पड़ा है। जनसंख्या की अधिकता के कारण पूँजी प्रधान तकनीकों को नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि श्रम की पूर्ति व तकनीक का उपयोग करना आवश्यक होता है, इस कारण भी हमारे देश में विकास की गति धीमी पायी जाती है।

(iii) देश में जनसंख्या वृद्धि का कृषि विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे जहाँ एक ओर कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भूमि के उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या देश के समक्ष उपस्थित होती जा रही है। इस कारण देश में भूमि की उत्पादकता में कमी हुई है।[5]

(iv) जनसंख्या तथा खाद्यान्न पूर्ति में प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। अतएव जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्न पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ता है जो स्वयं में एक समस्या मानी जाती है। इससे खाद्य समस्या का जन्म होता है।

(v) जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि से वस्तुओं की माँग में यकायक वृद्धि हुई है, किन्तु देश में उत्पादन की मात्रा में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। इससे योजना व्यय में वृद्धि हुई है।

(vi) जनसंख्या की वृद्धि से देश में भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस वृद्धि के कारण देश में निर्यात योग्य वस्तुओं की कमी बनी रहती है तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं को अधिक मँगाना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के सामने भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इससे समय-समय पर अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ा है।

(vii) जनसंख्या वृद्धि से देश में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, अर्द्ध-बेरोजगारी तथा मूल्य वृद्धि की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जल-पूर्ति का अभाव विशेष रूप से पाया जा रहा है। इससे हमारी विकास योजनाएँ बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं तथा हमारे विकास की गति धीमी हो गयी है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं है, वरन् पूँजी निर्माण की मात्रा को भी निर्धारित करता है।[4]

जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय :

जनसंख्या नीति से आशय उस सरकारी मान्यता से है, जिसके अनुसार जनसंख्या के आकार तथा संरचना को अपनाया जाता है। इसके माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जाता है। यह नीति सभी देशों में एकसमान नहीं होती है। इसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहता है। भारत में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद जनसंख्या की नीति का सम्बन्ध जन्म-दर पर नियन्त्रण कायम करना रहा है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं-

(i) राज्य सरकारें अनिवार्य बन्ध्याकरण से सम्बन्ध बनाकर इसे अनिवार्य बना सकती है।

(ii) समाज के निर्धन वर्ग को परिवार नियोजन के मौद्रिक सहायता में वृद्धि करनी चाहिये।

(iii) विवाह की आयु में वृद्धि की जानी चाहिये। इससे सन्तानोत्पत्ति में कमी आयेगी।

(iv) महिला शिक्षा में वृद्धि होने पर प्रजनन दर में स्वतः कमी हो जाती है।

(v) परिवार नियोजन कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाना चाहिये।

(vi) समूहों को प्रेरणा परिवार नियोजन हेतु पुरस्कार देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(vii) यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों के पाठ्यक्रमों में जनसंख्या सम्बन्धी बातों का समावेश किया जाना चाहिये।

अन्य सुझाव –

जनसंख्या नियन्त्रण के सम्बन्ध में कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार दिये जाते हैं-

(i) भारत में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु व्यापक पैमाने पर शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिये, ताकि जनसंख्या के वृद्धि के प्रभाव को आसानी से समझ सके।

(ii) विवेकहीन मातृत्व पर रोक लगायी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि सभी राज्यों को कानून बनाना चाहिये, ताकि बच्चे कम-से-कम उत्पन्न हों।

(iii) कुछ विद्वानों का विचार है कि विश्व के जिन देशों में जनाधिक्य है वहाँ से जनसंख्या को कम जनसंख्या वाले देशों में प्रवास की अनुमति दी जानी चाहिये।[3]

(iv) जनाधिक्य जनसंख्या का एक व्यावहारिक हल यह है कि कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन तीव्र गति से बढ़ाया जाये। इसे जनसंख्या नियन्त्रण का सकारात्मक उपाय कहा जाता है।

(v) देश में सुरक्षात्मक कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिये। इससे वृद्धावस्था या संकटकाल में सहारा पाने की दृष्टि से सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति को ठीक प्रकार से नियन्त्रित किया जा सके।

(vi) जनसंख्या व्यवस्था का वास्तविक तथा स्थायी हल यह कि प्रत्येक पुरुष के लिये दो या तीन बच्चे के बाद ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बनाया जा सकता है।[2]

(vii) एक जनसंख्या नियोजन आयोग स्थापित किया जाना चाहिये। इस आयोग का कार्य जनसंख्या नियन्त्रण करने की नीति निश्चित करना तथा उसे क्रियान्वयित करने के उपाय करना चाहिये।

उपर्युक्त तत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तव में देश का आर्थिक विकास राष्ट्रव्यापी, शीघ्र तथा प्रभावशाली जनसंख्या नियन्त्रण कार्यों पर निर्भर करता है।[8]

संदर्भ

1. "Total Population - Both Sexes". World Population Prospects, the 2014 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. July 2014. मूल से 22 दिसंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 June 2014.
2. ↑ "Birth Rate, Death Rate, Infant Mortality Rate and Total Fertility Rate: India and States". National Commission on Population, Govt of India. 2010. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जनवरी 2013.
3. ↑ "Census India SRS Bulletins". Registrar General of India, Govt of India. 2011. मूल से 13 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जनवरी 2013.
4. ↑ "Census India SRS Bulletins". Registrar General of India, Govt of India. 2013. मूल से 18 जनवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जनवरी 2013.
5. ↑ "Soutik Biswas's India: India's census: The good and bad news". BBC. 31 March 2011. मूल से 27 जनवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2011-09-24.
6. ↑ "India set to overtake China as world's most populated country after adding 180m people in a decade". Daily Mail. London. 31 March 2011. मूल से 11 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 जनवरी 2013.
7. ↑ US Census Bureau, Demographic Internet Staff. "International Programs – Information Gateway – U.S. Census Bureau". Census.gov. मूल से 11 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2011-09-24.
8. ↑ Based on P.N. Mari Bhat, "Indian Demographic Scenario ", Institute of Economic Growth, New Delhi, Discussion Paper No. 27/2001.